भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 658

06 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल की बिक्री में गिरावट

658. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 49.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान आरबीआई ने वाहन ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं/बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाहन ऋण पर ब्याज पर दरों में वृद्धि से खरीदार हतोत्साहित होंगे जिससे देश में ऑटोमोबाइल की बिक्री में गिरावट आएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में नए वाहनों की मांग में कमी के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या वाहनों की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): जी हां, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबिल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) से प्राप्त सूचनानुसार, पिछले कैलेंडर वर्ष अर्थात 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 49.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रेणी	कैलेंडर वर्ष 2022	कैलेंडर वर्ष 2023	% वृद्धि
दुपहिया	6,31,464	8,59,376	36.09%
तिपहिया	3,52,710	5,82,793	65.23%
वाणिज्यिक वाहन	2,649	5,673	114.16%
यात्री वाहन	38,240	82,105	114.71%
कुल	**10,25,063**	**15,29,947**	**49.25%**

स्रोत: एफएडीए अनुसंधान

(ख) से (घ): वाहन ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि/कमी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि/कमी से जुड़ी होती है। रेपो दर पिछले पुनरीक्षण अर्थात् 08 फरवरी, 2023 के बाद से 6.50% पर बनी हुई है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन स्कीम बनाई गई हैं:

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण** (फेम इंडिया): सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से प्रारंभ में 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि हेतु फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को अधिसूचित किया जिसे बाद में बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया।

ii. **ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम**: सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से मोटर-वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 18% तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

iii. **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम, 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम'**: सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 12, मई 2021 को पीएलआई स्कीम अनुमोदित की है। इस स्कीम में, देश में 50 गीगावॉट घंटे क्षमता वाली प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इस स्कीम में 5 गीगावॉट घंटे की उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है।

इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।

ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट देने और परमिट आवश्यकताओं से छूट देने की घोषणा की है।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ङ) : जी हां। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में कमी के लिए निम्नांकित अन्य कारकों को उत्तरदायी माना हैः

i. तदनुरूपी अंतर्दहन (आईसी) इंजन वाले वाहन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन की अग्रिम लागत का अधिक होना।

ii. इलेक्ट्रिक वाहन की रेंज के संबंध में ग्राहकों की चिंता।

iii. आईसीई वाहनों की तुलना में भारत में सीमित मॉडल उपलब्ध हैं-- विशेषकर इलेक्ट्रिक कार खंड में।

(च) : जी नहीं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कोई मंदी नहीं देखी गई है। ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों का कैलेंडर वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

कैलेंडर वर्ष	2020	2021	2022	2023
कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन	1,24,689	3,31,679	10,25,187	15,31,444

****